The Uttarakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation and Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums Located In the Urban Local Bodies of the State Act, 2016

Act No. 18 of 2016
सरकारी गजट, उत्तराखंड
उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण
विधायी परिषिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखंड अधिनियम)
देहरादून, बुधवार, 10 अगस्त, 2016 ई0
शासन 19, 1938 शक सम्मत
उत्तराखंड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 229/विधायी एवं संसदीय कार्य/26(1)2016
देहरादून, 10 अगस्त, 2016
अधिसूचना
विविध
“भारत का संविधान” के अनुसार 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखंड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितकरण, पुनर्वासन, पुनर्निर्माण एवं अतिक्रमण निषेध विधेयक, 2016 को दिनांक 05 अगस्त, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखंड अधिनियम संख्या 18, सन 2016 के रूप में सर्व-साधारण की सूचना में इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
उत्तराखंड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितकरण, पुनर्वसन एवं पुनर्योगिता एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम, 2016

(उत्तराखंड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2016)

उत्तराखंड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों में निवासस्तर परिवारों के जीवन स्तर के सुधार करने, इन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएँ विकसित करने, अध्यायित भू-खण्डों के विनियमितकरण एवं जहां आवश्यक हो, उनका पुनर्वसन एवं पुनर्योगिता की कार्यवाही किये जाने तथा भविष्य में नई मलिन बस्तियों की बसावट पर रोक लगाये जाने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में उत्तराखंड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखंड राज्य की नागर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितकरण, पुनर्वसन एवं पुनर्योगिता एवं अतिक्रमण निषेध अधिनियम, 2016 है।

(2) यह अधिनियम राज्यपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा तथा राज्य की समस्त नागर निकायों में लागू होगा।

2. “बस्ती” से नागर निकायों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र अभिभ्रष्ट है जहां आत्मविश्वास नहीं, अनियमित निर्माण, मूलभूत सुविधाओं एवं भौतिक अधिकारों के अभाव के कारण जहां स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से मानव बसावट अनुपयुक्त हो तथा जो उपरोक्त एक या एक से अधिक कारकों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये हों।

3. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

इस अधिनियम के उपक्रमों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अनुपस्थित किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखित में असंगत किसी विधि के होते हुए भी, प्रभाव होगा।

4. नियम बनाने की शक्ति

राज्य सरकार मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितकरण, पुनर्वसन, मूल्य/शुल्क का निर्धारण तथा मान्यता में नई मलिन बस्तियों की बसावट पर रोक लगाये जाने के लिए संगठन विषयों में अपनी अधिकारिता के अधीन नियम बनाने की ऐसी शक्ति ऐसी होगी जैसा विभिन्न की जाय।

5. नियम तथा दण्ड

राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत अधिसूचित मलिन बस्तियों को छोड़कर दिनांक 11.03.2016 के पश्चात बसने वाली मलिन बस्तियों पूर्ण रूप से प्रतिविधित होंगी तथा इन बस्तियों को अव्यवस्थित/अप्रतिशुल्क रूप से बसने एवं बसाने में सहयोग करने वाले को विरुद्ध इस कृत्य के लिए 06 माह के कारावास का दण्ड का भागीदार होगा तथा अपूर्व कोशिष्ट दण्ड के प्रतिदिन रूप 500/- अर्थ दण्ड भी कसूला जायेगा।

यह भी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मलिन बस्तियों में दिनांक 11.
03.2016 के पश्चात कोई व्यक्ति/परिवार अध्यासन करता है अथवा कराता है और अधिसूचित मलिन वस्तियों में बन्दोबस्त/पुनर्वास/पुनर्वर्षण के पश्चात अवध रूप से अध्यासन करता है अथवा कराता है तो उपरोक्तानुसार दण्ड के भारीदार होंगे।

इस अधिनियम के, या इस अधिनियम के अधीन बने किसी नियम के अधीन किया गया प्रतीत होने वाला कोई कार्य, यदि सद्भाव से और इस अधिनियम के द्वारा या अधीन लगाये गये कर्तव्यों के पालन या सौंपे गये कार्यों के सम्मादन में किया गया हो, उसके विषय में किसी अधिकारी या सरकारी सेवक पर कोई सिविल या फौजदारी कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

इस अधिनियम के किसी प्रावधानों के कारण या इस अधिनियम के या उसके अधीन बने किसी नियम के अनुसार सद्भाव से की गयी या की जाने को अभिप्रेत किसी बात से हुई या हो सकने वाली क्षति या अन्य हानि के सम्बंध में राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कोई दूसरी कार्यवाही नहीं चल सकेगी।
The Uttrakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation and Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums located in the Urban Local Bodies of the State Act, 2016

[Uttrakhand Act No. 18 Of 2016]

An Act

for reform, regulations, rehabilitations and resettlement of the Slums in the Urban bodies of the State of Uttarkhand

It is hereby enacted by the Uttrakhand Legislative Assembly in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. **Short title and commencement**
   
   (1) This Act may be called the Uttrakhand Reforms, Regularization, Rehabilitation and Resettlement and Prevention of Encroachment of the Slums located in the Urban Local Bodies of the State Act, 2016.

   (2) It shall come into force from the date of publication in official Gazette and shall be applicable in all the urban local bodies.

2. **Definition**

   ‘Slum’ shall mean those areas located within the local body which due to overcrowding, unplanned construction, lack of basic infrastructure and lack of tenurial rights are unfit for human habitation for reasons of health and security and for the above any one or a combination of factors have been notified by the State Government.

3. **Act to have overriding effect**

   The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

4. **Power to make rules**

   The State Government have such powers to make rules under his jurisdiction in relevant subject for reform, Regularization, rehabilitations and resettlement of the Slums as may be prescribed.

5. **Prohibition and Punishment**

   Except for the slums notified by the State Government under this Act, any settlement after 11 March, 2016 shall be completely prohibited. Any person directly or indirectly associated with settling or assisting in settling in such slums shall be punished with six months of imprisonment and an amount of Rs 500/- per day shall be recovered from the illegal occupier.

   If any person/family settles or assists in settling any other person/family in the slums notified by the State Government after 11 March 2016 or if any person/family settles illegally or assists in settling any other person/family in the slums which have been settled by bandobast / relocated or resettled by the State Government shall
be punishable with the above sentence.

6. No officer or servant of the Government shall be liable in any civil or criminal proceeding in respect of any act done or purporting to be done under this Act or under any rules made thereunder, if the act was done in good faith and in the course of execution of the duties or the discharge of functions, imposed by or under this Act.

   No Suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of any provisions of this Act or by anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.